से लागू किया गया है, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में पेट्रोल चालित नए चार पहिया वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया है। दिसम्बर, 1998 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को शामिल किया जाएगा। 1.4.2000 तक इसे पूरे देश में चलाया जाएगा।

(6) प्रमुख औद्योगिक और अन्य गतिविधियों के लिए स्थल निर्धारण से पहले प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों पर आधारित पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

(7) वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित मानकों को अमल में लाएं।

(8) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों के लिए साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(9) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना में बड़ी और मझौली औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध आधार पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(10) सरकार ने देश के नगरों/शहरों में 24 औद्योगिक पॉकेटों/क्षेत्रों को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में पता लगाया है जहां प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस प्रयास शुरू किए गए हैं।

इन उपायों का अमल में लाने से महानगरों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने में मदद मिलेगी।

World Bank Afforestation Project in Madhya Pradesh

2151. SHRI SURYABHAN PATIL WAHADANE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some tribal districts in Madhya Pradesh have been selected for better forestation under a World Bank Project;

(b) whether it is also a fact that about 40,000 forest personnel from this State are being given special training by World Bank for this purpose; and

(c) if so, the details in this regard and Government's reaction in the matter?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) World Bank aided Madhya Pradesh forestry project Envisage afforestation activities in the tribal districts of Bastar, Sarguja, Mandla, Jhabua, Dhar and Khargone.

(b) Training is being imparted to forest officials of various ranks in different disciplines of forestry under the project. The number of personnel to be trained will depend on the progress of the project. However, the number of personnel to be trained is likely to be much below 40,000.

(c) The training is required to impart new and better skills in policy planning, silviculture, extension and participatory techniques to the forest officials to implement the project effectively.

Newsitem captioned "Enviornment Seminar"

2152. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards a newsitem captioned "Environemt Seminar" published in "The Tribune", dated 24th January, 1997; and